Telangana Today- 13- December-2021

NGRI team stumbles upon lost River Saraswati

Hyd-based institute locates a 45-km-long buried ancient river in Ganga-Yamuna Doab

M SAI GOPAL
Hyderabad

THE LOCATION OF THIS MAJOR ANCIENT RIVER THAT FALLS WITHIN THE REGION WHERE THE LOST RIVER OF SARASWATI WAS FLOWING IN THE PAST, ADDS A NEW PHYSICAL DIMENSION TO THE MYTHOLOGICAL RIVER

Researchers from Hyderabad-based National Geophysical Research Institute of India (NGRI) might have just located the lost Saraswati river.

In an airborne electromagnetic study, NGRI researchers have located a 45-km-long buried ancient river in the Ganga-Yamuna Doab, usually described as a tract of land between the confluence of two rivers.

The study, titled 'Airborne Electromagnetic Signatures of Ancient River in the Water-Stressed Ganga Plain, Prayagraj, India: A Potential Groundwater Repository', was conceptualised and led by NGRI Director Dr Virendra M Tiwari and published in the form of a research letter in American Geophysical Union (AGU) on December 1.

"An airborne electromagnetic study in the Ganga-Yamuna Doab, supplemented with drilling and logging data to address the groundwater crisis, has unravelled exhaustive aquifer information with a discovery of 45-km-long buried river, having dimensions comparable to those of Ganga and Yamuna," the researchers said in the paper.

The location of this ancient river that falls within the region where the lost river of Saraswati was flowing in the past, adds a physical dimension to the mythological river, they said.

EXCLUSIVE

The NGRI researchers employed an airborne electromagnetic study, which revealed the huge aquifer or the buried paleo river. The dimensions are comparable to those of Ganga and Yamuna rivers near Prayagraj. The ancient river is characterised by a porous and permeable structure and is hydrogeologically linked with Ganga and Yamuna through an underlying principal aquifer, researchers said.

Towards Himalayas

The ancient river is likely to be extending towards the Himalayas, the study which was originally taken up to explore an effective water management plan for sustained water availability following the rapid depletion and deterioration of groundwater in the Ganga River Basin, said.

The underlying aquifer might also hold a great promise for management of current declining groundwater resources in the Ganga-Jamuna region, the study by NGRI researchers said. (SEE PAGE 2)

The Hindu- 13- December-2021

Water level in Idukki declines

A CORRESPONDENT
IDUKKI

Water level continued to decline in the Idukki reservoir and on Sunday it fell to 2,400.52 ft.

A dam safety official said power generation remained high. There had been no rainfall in the catchment area for the past two days, he said. The water level, however, reached a record in December providing a healthy storage level. It was for the first time since the commissioning of the dam that the water level had moved above 2,400 ft in December, he said.

Water is at the blue alert level now. The power generation at the Moolamattom power house on Saturday was 14.828 mu.

At Mullaperiyar

The water level in the Mullaperiyar dam continued to be close to the maximum level of 142 ft on Sunday. Tamil Nadu has been keeping the level at the maximum for over a week. One shutter of the dam was kept open to 10 cm on Sunday releasing 144 cusecs of water to the Periyar. The average inflow to the dam on Sunday was 1,359 cusecs while the tunnel discharge was 1,867 cusecs.

Financial Express- 13- December-2021

₹9,802-crore Saryu Canal project inaugurated

PRIME MINISTER NARENDRA Modi inaugurated the ₹9,802-crore Saryu Canal National project in Uttar Pradesh's Balrampur district on Saturday. The project, which is the biggest in Uttar Pradesh, will benefit 25-30 lakh farmers in nine eastern UP districts, Jal Shakti Minister Mahendra Singh said. It will facilitate the irrigation of 14.04 lakh hectares of land and at the same time reduce the risk of floods in flood-prone areas of the region due to water flowing from Nepal, he said. Five rivers have been connected under this project, including Ghagra, Saryu, Rapti, Banganga and Rohin, while canals with a length of 6,600 km have been linked to the 318-km-long main canal.

Rajasthan Patrika- 13- December-2021

पत्रिका डे-स्पेशल
मंडे मेगा स्टोरी

जल जीवन मिशन

राजस्थान में 21% तो छत्तीसगढ़ में मात्र 15% घरों में नल का पानी

घर-घर नल-जल पहुंचाने में पिछड़ गए बड़े राज्य, छोटों ने मारी बाजी

गोवा, तेलंगाना, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी और हरियाणा में काम पूरा

बसंत मौर्य
patrika.com

मुंबई. देश की ग्रामीण आबादी को साफ पेयजल मुहैया कराने से जुड़ी केंद्र की हर घर नल लगाने की महत्त्वाकांक्षी योजना करीब ढाई साल की हो गई है। इस अवधि में लक्ष्य हासिल करने में राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई बड़े राज्य पिछड़ गए हैं। वहीं गोवा, तेलंगाना, पुडुचेरी व हरियाणा जैसे चार राज्यों और केंद्र शासित अंडमान निकोबार व दादरा नगर हवेली में टार्गेट पूरा हो गया है। कोरोना काल में 8 करोड़ 65 लाख घरों में नल लगाए गए हैं। लक्ष्य 2024 तक 19 करोड़ 22 लाख ग्रामीण घरों में पेयजल मुहैया कराना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उम्मीद जताई है कि समय के भीतर लक्ष्य हासिल कर लेंगे।

गुजरात में सितंबर का लक्ष्य... गुजरात के 12,910 गांवों में नल से जलापूर्ति हो रही है।

घर-घर@पेज09

क्या है योजना

3.60 लाख करोड़ का बजट तय किया है केंद्र सरकार ने। *बड़े राज्यों को आधी* रकम केंद्र से मिलेगी

19 करोड़ से ज्यादा घरों की *90 करोड़ से अधिक* आबादी को साफ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य।

15 अगस्त, 2019 को पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन का ऐलान किया।

लक्ष्य हासिल करने में अव्वल

बिहार	90%
पंजाब	90%
हिमाचल	90%
गुजरात	89%
महाराष्ट्र	67%

आंकड़े: लक्ष्य का प्रतिशत

लक्ष्य हासिल करने में पिछड़े

उत्तर प्रदेश	13%
प. बंगाल	15%
छत्तीसगढ़	15%
झारखंड	16%
राजस्थान	21%
मध्य प्रदेश	36%

आंकड़े: लक्ष्य का प्रतिशत

राजस्थान 29वें स्थान पर...

राजस्थान में 84 लाख नल लगाए जाने हैं। अब तक 10 लाख 145 कनेक्शन जारी किए गए हैं। 10 हजार 800 करोड़ के स्वीकृत बजट में से 2,345 करोड़ की पहली किस्त मिली है। राज्य में केवल 50 लाख कनेक्शन के लिए सतही पानी उपलब्ध है। बड़े बांधों से पेयजल मुहैया कराने की कवायद जारी है। नल कनेक्शन की संख्या में यह देश में 29वें पायदान पर है।

केस स्टडी: जो अब भी है नल से दूर
घंटों टैंकरों का इंतजार

अहमदाबाद में भगवतीनगर के ठाकुर प्रसाद और उनके जैसे हजारों लोगों को घंटों महानगर पालिका के टैंकरों का इंतजार करना पड़ता है। नौकरीपेशा लोग रोज ही ड्यूटी पर लेट पहुंचते हैं और उनकी तनख्वाह भी कट जाती है। जिस दिन टैंकर लेट होता है प्लास्टिक के कनस्तरों में एक किमी दूर से पानी का जुगाड़ करना पड़ता है। सरकार कई साल से कनेक्शन देने की बात कह रही है मगर पानी कब पहुंचेगा पता नहीं।

किसे-कितना बजट

उत्तर प्रदेश	10,870.5
प. बंगाल	6,998.97
गुजरात	3,410
मध्य प्रदेश	5,117
पूर्वोत्तर	9,262
महाराष्ट्र	7,064.41
छत्तीसगढ़	1,908.96

आंकड़े करोड़ रुपए

हर घर जल मिशन

15 अगस्त, 2019 को स्थिति
18.93 करोड़ कुल घर
3.23 करोड़ कनेक्शन

30 नवंबर 2021 की स्थिति
19.22 करोड़ कुल घर
8.59 करोड़ कनेक्शन

■ चालू वर्ष का बजट 50 हजार करोड़ रुपए ■ पिछले वर्ष 30,370 करोड़ रुपए

मध्यप्रदेश में...

जिलेवार टारगेट तय

मप्र में 44.51 लाख घरों में नल से पानी पहुंचाया गया है। प्रदेश के 1.22 करोड़ ग्रामीण **जिलेवार@पेज09**

Rajasthan Patrika- 13- December-2021

ये भी जानें

बांध सुरक्षा विधेयक को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल

हाल ही बांध सुरक्षा विधेयक-2019 को राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया। यह विधेयक अगस्त 2019 में लोकसभा में पारित हो चुका था। देश के सभी बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रख-रखाव से जुड़े बांध सुरक्षा विधेयक पर दशकों से चर्चा होती रही है जिस देश में ज्यादातर बांधों का निर्माण, संचालन और रख रखाव राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है, वहां इस कानून का प्रभाव देखना काफी अहम होगा। लम्बित विवाद फिर से उठ सकते हैं।

क्योंकि : जानना जरूरी है...

5 **हजार** दो सौ से ज्यादा बड़े और 450 निर्माणाधीन बांधों की सुरक्षा की आशा है। विधेयक दोनों सदनों में पारित हो गया है

07% **बड़े बांधों** में ही आपातकालीन कार्ययोजना मौजूद थी। सीएजी ने 2017 में जारी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में यह जानकारी दी थी

क्या है बांध सुरक्षा विधेयक में

विधेयक में प्रस्ताव हैं कि सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को एक समान बांध सुरक्षा प्रक्रिया अपनाने में मदद की जाएगी। इसका उद्देश्य है बांध विशेष को आपदा में गिरने-टूटने से बचाना और सुरक्षित संचालन के लिए संस्थागत व्यवस्था करना। कानून के तहत बांध सुरक्षा पर तीन साल की अवधि वाली एक राष्ट्रीय समिति गठित की जाएगी।

क्यों लाया गया विधेयक

देश के ज्यादातर बांध राज्यों द्वारा ही बनाए जाते हैं और वे ही इनका रख-रखाव भी करते हैं। कुछ बड़े बांध जैसे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन या भाखड़ा-नांगल परियोजना का रख रखाव भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन मंडल करता है। केंद्र सरकार देश के 5200 से ज्यादा बड़े व 450 निर्माणाधीन बांधों के लिए बांध सुरक्षा विधेयक लाई है।

राज्यों की आपत्ति

केंद्र सरकार ने 2016 में इस विधेयक पर राज्यों से फीडबैक मांगा था, तो तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने इस पर आपत्ति जताते हुए उन प्रावधानों पर सवाल उठाए थे, जो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के बारे में चर्चा करते हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी केंद्र सरकार की आलोचना की कि सरकार ने बांध सुरक्षा विधेयक पारित करने से पहले राज्य के हितों पर विचार नहीं किया। उन्होंने विधेयक को राज्य सरकारों के हित में नहीं बताया। कुछ राजनीतिक दलों का मानना है कि विधेयक के प्रावधान राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तमिलनाडु का कहना है कि इससे पड़ोसी राज्यों में उसके द्वारा स्थापित बांध भी प्रभावित होंगे, उनके संचालन व रखरखाव में भी समस्याएं आएंगी। तमिलनाडु की चिंता है कि वह बांधों पर नियंत्रण, स्वायत्तता और स्वामित्व संबंधी अपने अधिकार पुनः पाना चाहता है।

Rashtriya Sahara- 13- December-2021

विकास की नहर

नदी जोड़ो परियोजना को पिछले बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को खास अहमियत रखने वाली सरयू नहर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। पांच नदियों तथा नौ जनपदों को जोड़ने वाली इस राष्ट्रीय परियोजना का काम अस्सी के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन अंजाम तक पहुंचना चार दशक बाद संभव हुआ है। गोंडा सहित नौ जिलों के 6227 गांवों के लगभग 30 लाख किसानों के लिए यह नहर वरदान साबित होगी। इससे किसानों को महंगी सिंचाई समेत अनेक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। 1978 में बहराइच व गोंडा की सिंचन क्षमता के विस्तार के लिए घाघरा कैनाल नामक परियोजना का शुभारंभ हुआ था।

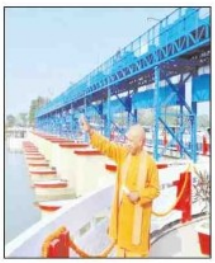

सुरसा की तरह परियोजना की लागत बढ़ती गई और काम भी पूरा नहीं हुआ। 1982 में परियोजना का विस्तार करते हुए अन्य जिलों को भी इसमें शामिल करके इसका नाम ट्रांस घाघरा-राप्ती-रोहिणी कर दिया गया। लेकिन बाद में इसका नाम सरयू नहर परियोजना कर दिया गया। करीब सवा लाख किमी. में फैली परियोजना के तहत जिले भर में 6,600 किमी. लंबी छोटी-बड़ी नहरों का जाल बिछ चुका है। इससे 15 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। क्षेत्र के किसान, परियोजना में अत्यधिक देरी की वजह से भारी नुकसान उठा रहे थे, परियोजना में पांच नदियों-घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ने का प्रावधान किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौ जिलों-बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज के किसान इससे लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री ने परियोजना में देरी के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इससे किसानों को सौ गुना ज्यादा कीमत भुगतनी पड़ी है। जब इस परियोजना की शुरुआत हुई थी तब इसकी अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपये थी। अब यह परियोजना लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के खर्च से पूरी हो सकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परियोजना का काम पूरा करने का श्रेय सत्तारूढ़ योगी सरकार द्वारा लेने पर तंज कसते हुए कहा है कि इस परियोजना का तीन चौथाई काम सपा सरकार के कार्यकाल में ही पूरा हो गया था। शेष बचे काम को पूरा करने में भाजपा सरकार ने पांच साल लगा दिए। जो भी हो इस नहर से क्षेत्र के विकास का नया अध्याय तो शुरू हो ही गया है।